भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3444

जिसका उत्तर मंगलवार 7 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

पर्यावरण हितैषी वाहन

3444. श्री अभिषेक सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक कितने ई-वाहनों का पंजीकरण हुआ है और इसके विनिर्माण को सस्ता बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ई-वाहनों के पर्यावरण हितैषी होने को ध्यान में रखते हुए ऐसे ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अलग से कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): नीति आयोग देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों का नेतृत्व और समन्वय कर रहा है।

फेम इंडिया स्कीम के चरण-1 के अंतर्गत अब तक मांग प्रोत्सान प्राप्त करने के लिए 110 ई-वाहन मॉडलों का पंजीकरण किया गया है। ई-वाहनों को सस्ता करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैः-

इलेक्ट्रिक वाहनों के निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कलपुर्जों पर मूल उत्पाद शुल्क (बीसीडी) से पूर्ण छूट उपलब्ध कराई गई हैः-

(क) बैटरी पैक

(ख) बैटरी चार्जर

(ग) एसी अथवा डीसी मोटर

(घ) एसी अथवा डीसी मोटर नियंत्रक

2. लिथियम ऑयन बैटरियों पर कर की दर को 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. इसरो ने इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लिथियम ऑयन सैलों से संबंधित अपेक्षित प्रौद्योगिकी विकसित की है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग हेतु भारतीय उद्योगों को लिथियम ऑयन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) किया है।

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि चार (4) अनुसंधान समूह (इसरो, सीएसआईआर, एआरसीआई और आईआईटी मुंबई) लिथियम ऑयन बैटरी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान कर रहे हैं। उन्हें निम्न लागत वाली लिथियम ऑयन बैटरी और वैकल्पिक बैटरी के लिए सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. फेम स्कीम के बल दिए जाने वाले प्रौद्योगिकी मंच (टीपीईएम) क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों, मोटर आदि के लिए हाई-पावर डीसी चार्जरों की डिजाइनिंग और विकास के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया।

******